PUNE RESEARCH TIMES ISSN 2456-0960
AN INTERNATIONAL JOURNAL OF CONTEMPORARY STUDIES VOL 3, ISSUE 4

शिक्षा और कामकाजजी महिलाओं का विकास

डॉ. छाया सुचक
मनोविज्ञान विभाग
विजयनगर आर्टस कोलेज,
विजयनगर, जि. साबरकांठा
गुजरात भारत

यह सत्य है कि आज अपेक्षाकृत अधिक संख्या में स्त्रियां, घर से बाहर निकल कर विभिन्न प्रकार के कार्य कर रही हैं लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू यह है कि आज भी अधिकतर औरतें निम्न स्तर के कार्यों में ही अधिक लगी हुयी हैं और ऊंचे ओहदे पर स्त्रियों की संख्या अपेक्षाकृत बेहद कम है । और इस दुर्भाग्यपूर्ण तथ्य के पीछे का कारण है, स्त्रियों में शिक्षा की कमी । औरतें, मिलों व कारखानों में मजदूरी करती हुई और निर्माण कार्यों में सिर पर ईंट ढोती तो आसानी से दिख जायेगी लेकिन कंपनियों या सरकारी कार्यालयों में ऊंचे ओहदों पर औरतों की संख्या बहुत कम है ।

शिक्षा की कमी के कारण औरतें, मजदूरी तो करती खूब दिख जाती हैं लेकिन निर्णय लेने वाले पदों पर उनकी ताजापोशी कम ही दिखती है । हमारी अधिकतर कामकाजी औरतें अल्पशिक्षित या अनपढ़ होती है जिससे स्पष्ट हो जाता है कि अधिकतर कामकाजजी महिलाएं, निम्न स्तर के कार्य ही करती हैं । पढ़ी-लिखी औरतों में से लगभग 68 फीसदी स्नातक स्त्रियां, हमारे यहाँ नौकरी करती ही नहीं हैं और नौकरी करने के स्थान पर स्नातक महिलाएं घर पर रोटियां बनाती हैं, बच्चे पालती हैं । एक अध्ययन के मुताबिक, कुल महिला श्रम का लगभग 34 प्रतिशत, खेतिहर

मजदूर होती हैं और हमारे देश में सिर्फ 5.2 प्रतिशत महिलाएं ही नौकरी करती हैं । ऊपर से तुर्रा यह कि पुरुषों के मुकाबले औरतों के वतन में 27.6 फीसदी का भारी अंतर होता है । अगली पंक्तियों में हम पढ़ेंगे कि भारत में स्त्रियों की शिक्षा की क्या स्थिति है और स्त्री-शिक्षा को बढ़ाने के लिए क्या प्रयास किये जाने चाहिएं ताकि महिलाएं भी ऊंचे पदों पर सुशोभित होकर अपनी निर्णायक भूमिका अदा कर सकें ।

शिक्षा व्यक्ति के सर्वांगीण विकास, सामाजिक और राष्ट्रीय-प्रगति तथा सभ्यता व संस्कृति के उत्थान के लिए अत्यंत आवश्यक है । इसके बिना किसी भी प्रकार के विकास की बात करना भी बेईमानी है । शिक्षा प्रकाश का वह स्त्रोत है जो जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में हमारा सच्चा पथ-प्रदर्शन करती है । विद्वानों का मत है कि ज्ञान मनुष्य का तीसरा नेत्र है और यह तीसरा नेत्र समस्त तत्वों के मूल को समझने की क्षमता प्रदान करता है एवं उसे उचित व्यवहार करने में प्रवृत्त करना है । शिक्षा से हमें संसार में सुख, समृद्धि एवं सुयश प्राप्त होता है और परलोक में मोक्ष । शिक्षा से हमें संसार में सुख, समृद्धि एवं सुयश प्राप्त होता है और परलोक में मोक्ष । शिक्षा से हमें एक ऐसे प्रकाश की प्राप्ति होती है जो हमारे सभी प्रकार के संशयों का उन्मूलन कर देता है । शिक्षा से हमें एक ऐसा सही दृष्टिकोण भी प्राप्त होता है जिसके कारण हमारी बुद्धि, विवेक, कौशल और निपुणता में वृद्धि होती है । यह शिक्षा का महत्त्व ही है कि भारतीय विद्वान भर्तृहरि ने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ "नीतिशतक" में कहा है कि विद्याहीन मनुष्य, पशु के समान है ।

वैदिक काल में ही शिक्षा के महत्त्व को समझ लिया गया था इसलिए उस समय शिक्षण और शिक्षा को मानव जीवन में सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण माना गया था । इस संदर्भ में अलतेक लिखते हैं कि वैदिक काल में शिक्षा के मुख्य उद्देश्य ईश्वर-भक्ति और धार्मिकता की भावना का विकास, चरित्र-निर्माण, व्यक्तित्व का विकास, नागरिक तथा सामाजिक कर्तव्यों का पालन, सामाजिक कुशलता की उन्नति तथा राष्ट्रीय संस्कृति का प्रसार-प्रचार आदि थे । वैदिक काल में महिलाओं को पुरूषों के

समान ही अधिकार प्राप्त थे इसलिए उस समय भी महिला-शिक्षा पर बेहद ध्यान दिया जाता था । वैदिक काल से लेकर आज तक महिला-शिक्षा का महत्त्व कम नहीं हुआ है लेकिन उसकी स्थिति में लगातार गिरावट ाती रही है । आज के आधुनिक युग में महिला-शिक्षा का अत्यधिक महत्त्व है लेकिन फिर भी हमारे देश में महिला शिक्षा की स्थिति बेहद खराब है । भारतीय महिलाओं के बीच शिक्षा का बेहद अभाव है जिस कारण वे लगातार हर क्षेत्र में पिछड़ती जा रही हैं । शिक्षा के बिना न तो महिला जागरूक हो सकती है और नही सशक्त ।

महिला सशक्तीकरण के लिए हमारे यहां काफी प्रयास किए जा रहे हैं लेकिन वास्तविकता क्या है, यह सभी जानते हैं । सवाला है कि क्यों महिलाए आगे नहीं बढ़ पा रही हैं, क्यों वे समाज और राजनीति में अपना स्वतंत्र अस्तित्व नहीं बना पा रही हैं । महानगरों में महिलाओं की स्थिति को देख कर लगात है कि महिलाएं काफी विकसित हो गयी है लेकिन यह सच नहीं है । वास्तव में आम महिलाओं के लिए विकास आज भी दूर की कौड़ी ही है । दूर दराज के ग्रामीण इलाकों की महिलाओं की स्थिति तो और भी खराब है । महिलाओं की इस बदहाल स्थिति का बस एक ही कारण है - शिक्षा की कमी, जगरूकता की कमी । स्पष्ट है कि महिला सशक्तीकरण की दिशा में सबसे बड़ा रोड़ा, महिलाओं में शिक्षा और जागरूकता की कमी ही है । यदि महिलाओं को शिक्षित बना दिया जाए तो वे अपने सामाजिक और राजनैतिक अधिकारों के प्रति जागरूक हो जायेंगी और फिर ऐसी जागरूक महिलाओं को दबाना, किसी के लिए भी संभव नहीं रह पायेगा । आज अगर औरतें समाज और राजनीति में सबसे पिछले पायदान पर खड़ी दिखायी देती हैं तो इसका सबसे प्रमुख कारण है औरतों के बीच शिक्षा की कमी । सन् 1951 में भारत में साक्षरता-दर मात्र 18.33 प्रतिशत थी जो अब बढ़कर 50 प्रतिशत से भी ऊपर हो गयी है । देखने में तो यह विकास का लक्षण प्रतीत होता है लेकिन तथ्य यह है कि हमारे यहां पुरुष साक्षरता जहां 64 फीसदी है वहीं महिलाओं के बीच साक्षरता की दर मात्र 40 फीसदी ही है ।

आज समूचे देश में बालिकओं के लिए मुफ्त शिक्षा का प्रावधान है लिकेन फिर भी बहुत सी बालिकाएं स्कूल के दरवाजे तक नहीं पहुंच पाती हैं । जो बालिकाएं किसी तरह स्कूल पहुंच भी जाती हैं वे आगे अपनी पढ़ाई जारी नहीं रख पाती हैं । कन्याओं का बेहद मामूली सा प्रतिशत ही कालेजों का मुंह देख पाता है तो इसका कारण कही न कहीं हमारी सामाजिक संरचना में छिपा है । बीच में ही स्कूल छोड़ देने की दर लड़कों की अपेक्षा लड़कियों में अधिक है तो िसका कारण यह है कि स्कूल के साथ-साथ उन पर घर के कामों का बोझ भी लाद दिया जाता है । यदि बालिका-शिक्षा नहीं और औरतें जागरूक नहीं तो फिर महिला विकास और सशक्तीकरण की बात करना भी बेमानी है । किसी भी देश का वास्तव में विकास तबी संभव है जब वहां की सम्पूर्ण आबादी का उसमें योगदान हो । भारत में जब 'आधी आबादी' के हिस्से की शिक्षा ही पूरी नहीं है तो फिर किस प्रकार वे देश की उन्नति में हाथ बटां सकीत हैं ? विकास कार्यों में और देश की उत्पादकता में औरतों का प्रतिनिधित्व जरूरी है । विकास का आधार शिक्षा ही तो है िसलिए महिलाओं की सम्पूर्ण क्षमता का इस्तेमाल करने के लिए जरूरी है कि वे साक्षर हों और वास्तविक रूप से शिक्षित हों । कुल आबादी में कामकाजी महिलाओं का प्रतिशत बढ़ाने के लिए भी महिला शिक्षा आज वक्त की जरूरत है ।

महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए जरूरी है कि महिला-शिक्षा को दो बागों में बांटा जाए-प्रारम्भिक साक्षरता और कार्यात्मक साक्षरता । प्राम्भिक साक्षरता कार्यक्रम से अधिक से अधिक ग्रामीण महिलाओं को जोड़ा जाना चाहिए ताकि महिलाएं अपने पैरों पर खड़ी हो कर देश के आर्थिक विकास में अपना योगदान दे सकें । साक्षरता को किसी भी समाज में सामाजिक व आर्थिक विकास का प्रतीत माना जाता है । सामाजिक, राजनैतिक व सांस्कृतिक चेतना तथा आर्थिक विकास के लिए उच्च साक्षरता दर और शिक्षा की गुणवत्ता बेहद आवश्यक है लेकिन दोनों ही मोर्चो पर भारत बुरी तरह से पिछड़ा हुआ है । महिलाओं की शिक्षा की स्थिति तो और भी

खराब है । पहले तो प्रारंभिक विद्यालयों में नामांकन कराने वाली बालिकाओं की संख्या ही अपेक्षाकृत बहुत कम है और फिर पांचवी कक्षा तक स्कूल छोड़ देने वाले विद्यार्थियों में भी बालिकाओं की संख्या अधिकतर है । भारत के सतत विकास का बस एक ही विकल्प है - बालिका शिक्षा ।

शिक्षा को अपने आप में साध्य और अन्य वांछनीय लक्ष्यों की पूर्ति का साधन समझा जाता है । शिक्षा के कारण व्यक्ति को बुद्धि का विकास होता है और उसका व्यक्तित्व निखरता है । इसके कारण व्यक्ति की सामाजिक व आर्थिक स्थिति तो सुधरती है है साथ ही उसमें सांस्कृतिक समझ भी विकसित होती है । शिक्षा के कारण समाजीकरण की प्रक्रिया को गति मिलती है और समाज में गतिशीलता आती है । वैसे तो समाज के प्रत्येक व्यक्ति और हर वर्ग के लिए शिक्षा एक ऐसा सशक्त उपकरण है जो नई समाज व्यवस्था का सृजन करने के लिए महिलाओं को सक्षम बनाता है । इसें हमारी सभ्यता और संस्कृति की सर्वोच्चता ही कहा जायेगा कि हमारे वेदों में भी महिला शिक्षा का विशद वर्णन है । सभी चार वेदों में महिला संबंधी सैकड़ों मंत्र दिए गए हैं जिनसे पता चलता है कि वैदिक काल में महिलाएं समाज में विशेष स्थान पर प्रतिष्ठित थीं । हमारे धर्म ग्रंथों के अनुसार प्राचीन काल में महिलाओं की शिक्षा की उत्तम व्यवस्था थी और राजनीतिक, सामाजिक, व प्रशासनिक गतिविधियों में भी महिलाओं की सक्रिय भागीदारी थी ।

यह महिलाओं में शिक्षा की कमी ही के कारण है कि उनके खिलाफ विभिन्न प्रकार के अत्याचार और दुर्व्यवहार होते हैं । भारतीय राजनीति में महिलाओं का प्रतिनिधित्व न के बराबर है तो इसका कारण भी शिक्षा और जागरूकता की कमी ही है । राजनीति और सत्ता में भागीदारी रूपी बैरोमीटर से किसी भी समाज के विकास का आकलन आसानी से किया जा सकता है क्योंकि सत्ता में भागीदारी होगी तो अधिकार होंगे और प्राप्त-अधिकार ही विकास का सबसे अच्छआ सूचक होते हैं । आज के राजनीति-प्रधान समाज में किसी भी वर्ग का राजनैतिक प्रतिनिधित्व बहुत मायने

रखता है लेकिन दुर्भाग्य से भारतीय राजनीति में महिलाओं का प्रतिनिधित्व बहुत कम है, लगभग नगण्य ही है । कुछेक नामों को छोड़ दें तो भारत का राजनैतिक पटल लगभग महिला-विहीन ही है । यदि राजनीति में प्रतिनिधित्व नहीं है, सत्ता में भागीदारी नहीं है तो फिर कैसा विकास ? इस प्रकार महिला-विकास के लिए भी महिला-शिक्षा महत्त्वपूर्ण है और आवश्यक है ।

राजनीति में कुछ महिलाएं सक्रिय है भी तो वे अपने प्रमुख रिश्तेदारों की डमी मात्र हैं । अल्पशिक्षित महिलाओं को उनके प्रमुख डमी या मुखौटे के रूप में इस्तेमाल करते हैं और निरीह महिलाओं को यह अत्याचार चुपचाप सहना पड़ता है क्योंकि शिक्षा की कमी के कारण उनमें अपने अधिकारों के प्रति चेतना नहीं है । गाँव और छोटे शहर-कस्बों के स्तर पर तो स्थिति बेहद खराब है । सवाल है कि राजनीति में महिलाएं 'डमी' क्यों हैं, क्यों वे दूसरों के इशारों पर नाचती हैं, क्यों वे स्वतंत्र रूप से कोई निर्णय नहीं ले पाती हैं और क्यों वे कोई अंतिम फैसला लेने से पूर्व पुरुषों का मुंह ताकती हैं ? महिलाओं की इस दुरावस्था का एक प्रमुख कारण है उनकी बदहाल शैक्षणिक स्थिति । शिक्षा द्वारा ही इस स्थिति को सुधारा जा सकता है । इसके अलावा महिलाओं की इस बदहाल स्थिति के लिए जिम्मेदार पुरुषों की सामंती प्रवृत्ति भी है । यह स्थिति अब बदलनी चाहिए और इसका बस एक ही उपाय है बालिका शिक्षा ।

अब चारों ओर महिला आरक्षण की धूम है । कोई इसके समर्थन में अपनी रोटियां सेंक रहा है तो कोई इसके विरोध में अपनी खिचड़ी पका रहा है । महिला आरक्षण की मांग और इसके विरोध में माहौल में इस बात पर चर्चा करना आवश्यक है कि कैसे राजनीतिक रूपमें आजगरूक किया जाए ? कुछ लोगों का मानना है कि महिलाओं के लिए विधायिका में आरक्षण लागू कर देने मात्र से महिलाएं, पुरुषों के समकक्ष आ खड़ी होगी लेकिन ऐसा सोचना गलत है । मात्र आरक्षण मिलने से ही महिलाएं इस प्रगति लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगी, इसमें सन्देह है । वास्तव में विधायिका

में 33 प्रतिशत आरक्षण देने के साथ-साथ जरूरी यह भी है कि महिलाओं को राजनीतिक रप से जागरक किया जाए और उन्हें शिक्षित बनाया जाए । महिलाओं की 'आधुनिकता' और पुरुषों से 'बराबरी' का नारा लगाने वाले अगर वास्तव में महिलाओं को आगे बढ़ाना चाहते हैं, उन्हें उनका वाजिब हक देना चाहते हैं तो बस जरूरत है महिलाओं को जागरूक व शिक्षित बनने की । अगर महिलाओं के हाथ में किताबें थमा दी जाएं तो फिर उन्हें राजनीतिक अधिकारी देने नहीं पड़ेगे वरन् अपने अधिकार वे स्वयं छीन लेंगी क्योंकि कोई भी जागरूक वर्ग अपने अधिकारों का हनन बर्दाश्त नहीं कर पाता है ।

अगर बिना शिक्षा और जागरूकता के विधायिका मं महिलाओं को आरक्षण दिया गया तो संसद व विधानसभाओं का भी वहीं हाल होगा जजो हाल पंचायतों और नगर पालिकाओं का हुआ है । नगर पालिकों व पंचायतों में आरक्षण देकर ही हमने समझ लिया था कि अब महिलाएं भी आगे बढ़ सकेंगी, वे आगे बढ़ कर राजनीति में भागीदारी करेंगी, सत्ता में हिस्सेदारी करेंगी । लेकिन हुआ क्या, हम सभी अच्छी तरह से जानते हैं । निर्वाचित महिला सदस्यों के पति या अन्य पुरुष रिश्तेदारों ने ही उनके नाम पर राजनीति की । अधिकतर मामलों में महिलाएं घूंघट निकाल कर क्या बुर्का पहन कर, पुरुष रिश्तेदारों के हाथों की कठपुतली ही बनी रहती हैं । लोकतंत्र के इस मखौल का का एक प्रमुख कारण शिक्षा की कमी है । यह बिल्कुल सही है कि भारतीय संविधान ने महिला तथा पुरुषों को बीच लिंग के आधार पर कोई भेद नहीं किया है और दोनों को समान रूप में अधिकार दिए गए हैं । आजादी के बाद संविधान द्वारा लिंग-भेद की समस्त परंपराओं को दरकिनार करते हुए महिलाओं को भी समान अधिकार और समान सहभागिता के अवसर दिए गए हैं लेकिन महिलाएं अपने अधिकारों का प्रयोग धरातल पर नहीं कर पा रही हैं तो इसका कारण उनमें राजनैतिक व सामाजिक चेतना की कमी होना भी है और चेतना का सीधा संबंध

शिक्षा से होता है । अगर महिलाएं शिक्षित होंगी तो वे अपने अधिकारों के प्रति सजग भी होंगी और जागरूक भी । इस प्रकार महिला-शिक्षा बेदह महत्त्वपूर्ण है ।

संदर्भः

1. कामकाजी महिलाएं (वास्तविक स्थिति)

   डो. रेणु त्रिपाठी, डो. अर्पणा त्रिपाठी,

   खुशी पब्लिकेशन्स, नई दिल्ली - 22

2. स्त्री ओर समाज

   अन्डा प्रकाशन, अमदावाद

3. www.google.employswomen and development